शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2024 माह का मासिक सारांश:

माह अप्रैल, 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ

(i) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं (एचईआई), जिन्होंने विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में रैंक हासिल की है, के साथ एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई, । इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य संस्थाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना तथा अन्य संस्थाओं के लिए उन्हें अपनाने और लागू करने के माध्यम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने के अवसर प्रदान करना था। बैठक में शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग वाली संस्थाओं ने भी भाग लिया। विषयवार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, दिनांक 10 अप्रैल 2024 को जारी की गई। इस नवीनतम संस्करण में 69 विश्वविद्यालयों में 454 प्रविष्टियों के साथ भारत की उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है, जो विगत वर्ष की 355 प्रविष्टियों की तुलना में 19.4% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है।

(ii) भारत में परिसर स्थापित करने वाली विदेशी उच्च शिक्षा संस्थाओं के नियमों तथा संयुक्त उपाधि, युगल उपाधि और ट्विनिंग कार्यक्रम के नियमों के अनुरूप भारत में परिसर खोलने, संस्थागत सहयोग के अवसरों और अनुसंधान में सहयोग आदि पर विदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श किया गया। विदेश में स्थित विश्वविद्यालयों में मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया; ऑस्ट्रेलियाई नवीन अनुसंधान विश्वविद्यालय (आईआरयू) जैसे फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय, ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, जेम्स कुक विश्वविद्यालय, ला ट्रोब विश्वविद्यालय, कैनबरा विश्वविद्यालय और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय आदि शामिल थे। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय पहलों के लिए वाइस प्रोवोस्ट, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ स्वास्थ्य, सतत शहरों, कृषि, सतत ऊर्जा, फिनटेक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान आदि जैसे सहयोग के कई क्षेत्रों को शामिल करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आठ सदस्यों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 5(3)(ख) और 5(3)(ग) के प्रावधानों के तहत दिनांक 10.04.2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 7-2/2023-यू1ए के माध्यम से नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार, 24 केन्द्रीय वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं नामतः आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईईएसटी, सीयू आदि के निदेशकों/कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए।

(iv) शिक्षा क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं, विशेष रूप से छात्रावास के विकास से संबंधित बाजार संबंधी गतिविधियों को समझने के लिए दिनांक 25 अप्रैल 2024 को मुंबई में एक हितधारक परामर्श-सत्र आयोजित किया गया। उच्चतर शिक्षा विभाग आर्थिक कार्य विभाग की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना के तहत पीपीपी मोड में छात्रावास के विकास की संभावना तलाश रहा

है। आईआईटी मद्रास, आईआईआईटी नागपुर और आईआईएम उदयपुर ने छात्रावास के विकास हेतु अपनी पीपीपी पहलें प्रस्तुत की। बैठक में 18 अग्रणी कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख ऋणदाता, डेवलपर्स, छात्रावास संचालक, तथा बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट निवेशक शामिल थे।

(v) 'राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल (एनआईडीआई)' के कार्यान्वयन और 'डिजाइन एवं उद्यमिता हेतु क्षमता निर्माण' के साथ इसके तालमेल पर अध्ययन संबंधी नए और उभरते क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा अपनाए गए भावी कार्यों के 8 क्षेत्रों के अनुरूप बनाना; डिजाइन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानने के बजाय पाठ्यक्रम में शामिल करना; उद्यमिता को करियर के रूप में लेने वाले छात्रों के अनुपात में तीन गुना वृद्धि करना आदि उद्देश्यों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

(vi) आईआईटी और आईआईएससी के साथ गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन पद्धति पर एक सत्र दिनांक 10.04.2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि गुणवत्ता और अवसंरचना परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए क्यूसीबीएस का लाभ कैसे उठाया जाए। सत्र की शुरुआत आईआईटी-मद्रास द्वारा की गई थी। आरक्षण रोस्टर के रखरखाव पर केंद्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के संकाय की क्षमता निर्माण के लिए उसी दिन एक और ऑनलाइन सत्र भी आयोजित किया गया था।

(vii) 5 वर्ष और 100 दिन की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए सचिवों के क्षेत्रीय समूह की बैठक आयोजित की गई।

***